

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-मुख्य नगर अधिकारी/
नगर निगम, देहरादून।
2-मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी,
हरिद्वार, हल्द्वानी।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 28 जनवरी, 2013

विषय:-तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये
गये निर्णय के अनुसार नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2012-13 की चतुर्थ
त्रैमासिक किश्त का अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 03 नगर निगमों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु ₹ 158743000.00 (₹ पन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही है:-

(1) अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।


(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-191-नगर निगम-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा संलग्न बी0एम0-15 के कॉलम-4 की बचतों (अलोटमेन्ट आईडी-R1301070049) से वहन किया जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

आज्ञा से,


(एल.एन. पन्त)


अपर सचिव, वित्त।

संख्या-49 (1)/XXVII(1)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूँ मण्डल।
- 3- सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- जिलाधिकारी, जनपद- देहरादून/हरिद्वार/ नैनीताल।
- 5- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
- 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 9- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी.....।
- 10- एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,


(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: 49 /XXVII(1)/ 2013

दिनांक: 28 जनवरी, 2013

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर निगमों को
वित्तीय वर्ष 2012-13 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त का अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त
1	2	3	4
नगर निगम			
1-	देहरादून	देहरादून	88315 ✓
2-	हरिद्वार	हरिद्वार	42183 ✓
3-	नैनीताल	हल्द्वानी	28245 ✓
योग			158743

(रु० पन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख तैंतालीस हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
(बिहीन बर्ष 2012-2013)

बी.एम. - 15

जलोटेट कार्डी - RI30107/0049
दिनांक - 21-Jan-2013

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनिवेशन स्वीकृति क्रम संख्या -

क्रम संख्या	वस्तु प्रविष्टि का नाम (1)	मानक प्रत्यक्ष व्यय (2)	विहीन बर्ष के व्यय में अनुमानित व्यय (3)	आवश्यक सामग्री (4)	देवाधीन विद्यमान व्यय (5)	पुनर्विनिवेशन के बाद संख्या -5 की कुल व्यय (6)	पुनर्विनिवेशन के बाद संख्या -1 में कुल व्यय (7)	विवरण
1	20 - सहायक अनुदान/अनुदान/वस्तु 563900000	494802582	61697418	7400000	20 - सहायक अनुदान/अनुदान/वस्तु 7400000	642387000	556500000	
	3804 सार्वजनिक विकास कार्य परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत समर्थन 01 नगरपालिका विकास 183 नगरपालिका विकास परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत समर्थन 04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संयुक्त व्यय अनुदान 00 राज्य वित्त आयोग द्वारा संयुक्त व्यय (Non Plan Voted)				3804 सार्वजनिक विकास कार्य परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत समर्थन 01 नगरपालिका विकास 191 नगरपालिका विकास 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संयुक्त व्यय अनुदान 00 राज्य वित्त आयोग द्वारा संयुक्त व्यय (Non Plan Voted)			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनिवेशन से वस्तु प्रविष्टि 150,151,155,156 में उचित अतिरिक्त व्यय की गई है।

पुनर्विनिवेशन विवेक को हेतु प्रमाण 15 की तालिका में विहीन बर्ष 2012-2013 में उचित व्यय की गई है।

पुनर्विनिवेशन स्वीकृति ।

अवधि

(रज. रज. प्र.)

उत्तराखण्ड, बिना ।